Popular Front of India

G-78, 2nd Floor, Shaheen Bagh, Kalindi Kunj, Noida Road, New Delhi- 110025

PopularFrontofIndiaOfficial/ www.popularfrontindia.org

popularfrontmail@gmail.com 011- 29949902

प्रेस रिलीज़

20 जून 2019
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में बदलाव करने की पॉपुलर फ्रंट की मांग

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की केंद्रीय सचिवालय की बैठक में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किये गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में बदलाव करने की मांग की गई है। बैठक का कहना है कि यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की तैयारी है, जिससे विशेष रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ की पूर्ती होगी।

बैठक ने इस ओर इशारा किया कि एक तरफ जहां मसौदे में प्रस्तावित कुछ मौलिक सुधार, छात्रों के बोझ में इज़ाफा करते हैं, वहीं कुछ प्रस्ताव सरकार के असल इरादे को भी ज़ाहिर करते हैं कि सरकार शिक्षा पर अपनी पकड़ मज़बूत करना चाहती है।

मौजूदा वार्षिक परीक्षा व्यवस्था को बदलकर 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए आठ सेमेस्टर का सिस्टम शुरू करना चिंता का विषय है। वैसे ही इन कक्षाओं के लिए पढ़ाई के दिन बहुत कम मिलते हैं और स्कूल पहले ही अध्यापकों की कमी से परेशान हैं। इन समस्याओं का समाधान किये बिना सेमेस्टर सिस्टम शुरू करने से छात्रों का बोझ और बढ़ जाएगा।

प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग शिक्षा व्यवस्था को चलाने वाला सर्वोच्च निकाय होगा। इसके संविधान में शिक्षा से अधिक राजनीतिक लाभ का वर्चस्व होगा। इसके सिर्फ आधे सदस्य अपनी क़ाबिलियत के आधार पर चुने जाएंगे, जबकि बाकी सदस्यों का चयन मंत्रीमंडल करेगा। कमेटी के 50 प्रतिशत सदस्यों को संसद से लाने का प्रस्ताव साफ तौर पर यह बताता है कि शासक वर्ग के लाभ की पूर्ती के लिए इसमें राजनीती का बहुत ज़्यादा दख़ल होगा।

हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा तय करना भी एक अलोकतांत्रिक कदम है। हिंदी भाषा भारत के सभी राज्यों में नहीं बोली जाती। अतः सभी भाषाई आबादियों पर हिंदी भाषा को थोपना भारत की क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों के विकास में रूकावट का कारण होगा।

निजी सेक्टर्स को दी गई छूट से यह ज़ाहिर होता है कि सरकार शिक्षा संस्थानों से खुद को अलग करके सांठ–गांठ के द्वारा इन संस्थानों की निजकारी का काम कर रही है। ऐसे कॉलेजों को फीस, कोर्स और पाठ्यक्रम तय करने की पूरी आज़ादी दी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता लाने के बहाने किये गए सुधार आम शिक्षा प्रणाली को कमज़ोर और प्राइवेट सिस्टम को मज़बूती देंगे, जिसके नतीजे में वंचित वर्ग बिल्कुल गायब हो जाएंगे। गुणवत्ता और काबिलियत की बात करने के साथ–साथ यह मसौदा बड़ी आसानी से वंचित वर्गों के लिए संवैधान द्वारा दिये गए आरक्षण को नज़रअंदाज़ कर देता है।

'मिशन नालंदा' और 'मिशन तक्षशिला' तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक दृष्टीकोण को बढ़ावा देने के बजाए पुराने ज्ञान से असंतुलित प्रेम का पता देते हैं। हज़ारों सालों पहले मौजूद समझी जानी वाली रिवायत पर उच्च शिक्षा का ख़ाका तैयार करने की सिफारिश, शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश का हिस्सा है।

बैठक ने सभी राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों और छात्रों से यह अपील की है कि वे शासक वर्ग के द्वारा हमारी शिक्षा प्रणाली में राजनीतिक एवं कारोबारी दख़लअंदाज़ी और भगवाकरण की कोशिशों को हर हाल में रोकें।

चेयरमैन ई. अबूबकर ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें महासचिव एम. मुहम्मद अली जिन्ना, उपचेयरमैन ओ.एम.ए. सलाम, सचिव अब्दुल वाहिद सेठ व अनीस अहमद, ई.एम. अब्दुर्रहमान और के.एम. शरीफ मौजूद रहे।

एम. मुहम्मद अली जिन्ना
महासचिव
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया